पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

राज कुमार साह एवं अन्य

बनाम

चंद्रभान सिंह एवं अन्य

2023 का प्रथम अपील संख्या 57

28 नवम्बर 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

- क्या 187 दिनों की देरी को साक्ष्य और परिस्थितियों के आधार पर सीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत क्षम्य माना जा सकता है?
- क्या अनुपूरक हलफनामे में दी गई दलीलें प्रारंभिक आवेदन की अस्पष्टताओं को स्पष्ट करती हैं?
- क्या न्यायिक दृष्टिकोण में 'प्रमुख न्याय' की अवधारणा, कठोर प्रक्रिया आधारित अनुपालन पर प्राथमिकता रखती है?

हेडनोट्स

वर्तमान आवेदन में अपीलकर्ताओं द्वारा विलंब के कारण के रूप में जो परिस्थितियाँ बताई गई हैं, जिनके कारण वर्तमान अपील दाख़िल करने में 187 दिनों की देरी हुई, वे उक्त विलंब को क्षम्य ठहराने के लिए पर्याप्त हैं। (पैरा 5) ; यद्यपि प्रत्येक दिन के विलंब के लिए पृथक रूप से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, तथापि कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो इंगित करती हैं कि पैरवीकार एक वृद्ध व्यक्ति हैं और संबंधित अवधि के दौरान वृद्धावस्था संबंधी रोगों से पीड़ित थे; दूसरा, वह ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं; और तीसरा, उन्होंने यह दलील दी है कि संबंधित अवधि के दौरान अपीलकर्ताओं के पास अपील दायर करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं थी और धन एकत्र करने में कुछ विलंब हुआ। (पैरा 5)

न्याय दृष्टान्त

मोस्मत राम कली कुअर एवं अन्य बनाम इन्द्रदेव चौधरी एवं अन्य, ए आई आर 1985 पटना 148; मणिबेन देवराज शाह बनाम बृहन्मुंबई नगर निगम, (2012) 5 एस सी सी 157; एषा भट्टाचार्य बनाम रघुनाथपुर नफर अकादमी प्रबंध समिति, (2013) 12 एस सी सी 649; बसवराज एवं अन्य बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण

पदाधिकारी, (2013) 14 एस सी सी 81; कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, अनंतनाग बनाम मस्ट. कटीजी, **(1987) 2** एस सी सी **107**

अधिनियमों की सूची

सीमा अधिनियम, 1963 (धारा 5)

मुख्य शब्दों की सूची

सीमा अधिनियम; धारा 5; देरी शमन; प्रमुख न्याय; सद्भावना; प्रक्रिया संबंधी विलंब; ग्रामीण वादी; वाद संख्या; अनुपूरक हलफनामा; उदार व्याख्या

प्रकरण से उत्पन्न

वाद संख्या 282 / 2022, सिविल न्यायालय, जमुई

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ताओं की ओर से: श्री शब्बीर अहमद, अधिवक्ता

प्रतिवादियों की ओर से: श्री जे.एस. अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता,श्री प्रभात रंजन सिंह, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट्स बनाया गयाः अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का प्रथम अपील संख्या 57

==========

1. राज कुमार साह पिता स्वर्गीय दासो साह, निवासी मौजा-मलयपुर, थाना-मलयपुर, थाना-मलयपुर, अंचल-बाराहाट, जिला-जमुई।

2. राम चन्द्र साह पिता स्वर्गीय दासो साह निवासी मौजा-मलयपुर, थाना-मलयपुर, थाना-मलयपुर, अंचल-बाराहाट, जिला-जमुई।

3. श्याम सुन्दर साह पिता स्वर्गीय दासो साह निवासी मौजा-मलयपुर, पो0-मलयपुर, पो0- मलयपुर, अंचल-बाराहाट, जिला-जमुई।

4. संजय कुमार पिता स्वर्गीय दासो साह निवासी मौजा-मलयपुर, थाना-मलयपुर, थाना-मलयपुर, अंचल-बाराहाट, जिला-जमुई।

... ...अपीलार्थी

बनाम

1. चन्द्रभान सिंह पिता कन्हैया सिंह, निवासी ग्राम-दौलतपुर, थाना व जिला-जमुई

2. हरेन्द्र कुमार सिंह पिता स्व.प्रमोद कुमार सिंह, निवासी ग्राम-मलयपुर डाकघर-मलयपुर, थाना-मलयपुर, जिला-जमुई।

3. अनुज कुमार सिंह पिता श्री मुकेश कुमार सिंह, निवासी ग्राम-मलयपुर डाकघर-मलयपुर, थाना-मलयपुर, जिला-जमुई।

4. धर्मेंद्र सिंह पिता स्व.सीताराम सिंह, निवासी ग्राम-मलयपुर, पो.ओ.-मलयपुर, थाना मलयपुर, जिला-जमुई, वर्तमान में क्वार्टर नंबर 88/2/3 हाउसिंग कॉलोनी, हनुमान के पास, मंदिर छोटा गोविंदपुर, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम (झारखंड)।

5. कुमार सूरज पिता श्री किशोर कुमार मिश्रा, निवासी मलयपुर, पो.-मलयपुर, जिला-जमुई।

6. अशोक साव, पिता स्वर्गीय गणेश साव, निवासी- छत तालाब के पास, मनायतांड़, थाना-ओ एवं थाना-धनबाद, जिला-धनबाद (झारखंड)।

7. बिनोद कुमार पिता स्वर्गीय हीरा आरा, निवासी विद्युत बोर्ड कॉलोनी, रोड नं.01 बुद्धा कॉलोनी, पटना।

8. अजय साव पिता स्वर्गीय जगत साव, निवासी गायघाट बस्ती पारा, हरिपुर पांडेश्वर वर्धमान (पश्चिम बंगाल)।

9. मिंटू साव पिता स्वर्गीय जगत साव, निवासी हरिपुर, बगधा वर्धमान (पश्चिम बंगाल)

10. राजेश कुमार साव, पिता जगत साव, निवासी-नया बाजार दुर्गा मंदिर गली, लखीसराय, पोस्ट, थाना एवं जिला-लखीसराय।

11. संतोष साव पिता स्वर्गीय राजेंद्र साव, निवासी मौजा-मलयपुर, थाना-मलयपुर, थाना-मलयपुर, अंचल-बाराहाट, जिला-जमुई।

12. कृष्णा साव पिता स्वर्गीय सुरेश साह, निवासी मौजा-मलयपुर, थाना-मलयपुर, थाना-मलयपुर, अंचल-बाराहाट, जिला-जमुई।

13. बलराम साव पिता स्वर्गीय सुरेश साह, निवासी मौजा-मलयपुर, थाना-मलयपुर, थाना-मलयपुर, अंचल-बाराहाट, जिला-जमुई।

14. रमेश साव पिता स्वर्गीय भोलानाथ साह, निवासी मौजा-मलयपुर, थाना-मलयपुर, थाना-मलयपुर, अंचल-बाराहाट, जिला-जमुई।

15. उमेश साह पिता स्वर्गीय भोलानाथ साह, निवासी मौजा-मलयपुर, थाना-मलयपुर, थाना-मलयपुर, अंचल-बाराहाट, जिला-जमुई।

16. दिनेश साह निवासी मौजा-मलयपुर, थाना-मलयपुर, थाना-मलयपुर, अंचल-बाराहाट, जिला-जमुई।

... ... प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति :

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री शब्बीर अहमद, वकील।

प्रतिवादी/प्रतिवादियों के लिए : श्री जे.एस. अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता।

श्री प्रभात रंजन सिंह, अधिवक्ता

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र सिंह

मौखिक आदेश

28-11-2024 **<u>आई.ए. संख्या 01/2023</u>**

सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर तत्काल अंतरिम आवेदन इस अपील को दायर करने में हुई 187 दिनों की देरी को माफ करने के लिए अपीलकर्ताओं की प्रार्थना पर विचार के लिए लिया जाता है।

2. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री शब्बीर अहमद ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि अपीलकर्ताओं की ओर से वर्तमान अपील दायर करने में 187 दिनों का विलंब हुआ, परन्तु कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं जो उक्त विलंब को उचित ठहराती हैं। सबसे पहले, अपीलकर्ताओं द्वारा दायर टाइटल सूट संख्या 282/2022 पर ट्रायल कोर्ट द्वारा

29.09.2022 को सुनवाई की गई और उसी दिन आपत्तिजनक आदेश पारित किया गया, लेकिन अपीलकर्ताओं को उनके मुकदमे के परिणाम के बारे में अंधेरे में रखा गया और 06.10.2022 को, उन्होंने अपने मुकदमे को खारिज करने के बारे में एक अफवाह सुनी और फिर अपीलकर्ता सिविल कोर्ट, जमुई गए, 07.10.2022 को अपने विद्वान वकील से संपर्क किया और सुनवाई की पहली तारीख यानी 29.09.2022 को अपने मुकदमे को खारिज करने के तथ्य को जानने के बाद अत्यधिक आश्चर्यचकित हुए और अगली तारीख, 30.09.2022 क्लीयरेंस डे था और 01.10.2022 से 09.10.2022 तक *दुर्गा पूजा* उत्सव के कारण कोर्ट में छुट्टी थी। अपीलकर्ताओं ने दिनांक 29.09.2022 के निर्णय और आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए 07.10.2022 को अनुरोध दायर किया, जो अनुरोध दायर करने के दस दिन बाद 17.10.2022 को वितरित किया गया। अपील दायर करने के लिए निर्धारित सीमा अवधि की अंतिम तिथि 02.01.2022 थी, जिसमें न्यायालय में अवकाश तथा विवादित निर्णय की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने में हुई देरी को शामिल नहीं किया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि देरी का कारण स्पष्ट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति यह है कि अपीलकर्ता संख्या 1, *जोड़ीकर*, 66 वर्ष के हैं, वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं तथा सीमा अवधि के कानून की जानकारी न होने के कारण वे अपनी आर्थिक स्थिति के कारण तत्काल अपील दायर करने के लिए आवश्यक धनराशि का प्रबंध करने में असमर्थ थे, तथापि, उन्होंने आवश्यक धनराशि का प्रबंध किया तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान 06.06.2023 को पटना आकर अपने वकील को कानूनी उपाय करने का निर्देश दिया, इसलिए अपीलकर्ताओं की ओर से जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई तथा उन्हें उक्त अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण सीमा अवधि के भीतर वर्तमान अपील दायर करने से रोका गया तथा उक्त देरी को माफ किया जा सकता है। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने

इस न्यायालय द्वारा **मोस्मात राम काली कुएर एवं अन्य बनाम इंद्रदेव चौधरी एवं अन्य** के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा जताया है, जो एआईआर, 1985, पटना 148 में रिपोर्ट किया गया है, प्रासंगिक हिस्सा जिस पर भरोसा रखा गया है, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

> "9. न्यायालयों ने माना है कि यदि कोई अपील समय से पहले प्रस्तुत की जाती है और न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाती है, तो प्रतिवादी को अपील पर प्रारंभिक आपत्ति उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब मामला गुण-दोष के आधार पर लिया जाता है। आवेदन प्रस्ताव के माध्यम से किया जाना चाहिए। न्यायालय कभी भी लोगों को उनके अधिकार का इंतजार करने की अनुमति नहीं देगा, जबकि दूसरा पक्ष खर्च वहन करता है। एआईआर 1923 मैड 82 - मरुगप्पा नायकर बनाम थेयाम्मल देखें। इसके अलावा, यदि किसी स्पष्ट परिस्थिति में अपील प्रस्तुत करने में देरी के लिए औपचारिक या लिखित आवेदन के बिना अपील दायर की जाती है, तो न्यायालय को न्याय की विफलता से बचने के लिए पक्षों को मामले को सुधारने का उचित अवसर देना चाहिए (एआईआर 1975 मैड 137 मेघराज बनाम जेसराय कस्तूरजी और अन्य देखें।) कुछ मामलों में यह विचार किया गया है कि धारा 5 की भाषा यह प्रावधान नहीं करती है कि उक्त प्रावधानों के तहत राहत दिए जाने से पहले लिखित में आवेदन दायर किया जाना चाहिए। एआईआर 1936 सभी 666 देखें - माउंट कुलसुम उन-निसा बनाम नूर मोहम्मद। मुख्य न्यायाधीश सुलेमान जे. माउंट कुलसुम उन-निसा (उपर्युक्त) के मामले में पीठ की ओर से बोलते हुए सीमा के प्रश्न पर विचार करते हुए कहा:

> "..... हमारा मानना है कि निचली अदालत को प्रतिवादी को समय विस्तार के लिए औपचारिक आवेदन की अनुपस्थिति की तकनीकी आपत्ति को दरकिनार करने की अनुमति देनी चाहिए थी।"

3. दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जे.एस. अरोड़ा ने इस आवेदन का पुरजोर विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ताओं ने वर्तमान आई.ए. दायर करने में सद्भावना के साथ नहीं आए हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्रारंभिक आवेदन (आई.ए. संख्या 01/2023) में देरी का उचित कारण नहीं बताया है और उनके द्वारा लिया गया मुख्य आधार पूरी तरह से अस्पष्ट और भ्रामक था और फिर उन्होंने देरी के कारणों को स्पष्ट करने के लिए एक पूरक हलफनामा दायर किया और अस्पष्टता को दूर किया लेकिन फिर भी, इस आई.ए. और उनके पूरक हलफनामे में अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए कथनों के बीच गंभीर विरोधाभास हैं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि यद्यपि अपीलकर्ताओं ने अपने विलम्ब के संबंध में कुछ कारण बताए हैं, लेकिन यह केवल 17.10.2022 को समाप्त होने वाली अवधि के संबंध में है, जैसा कि स्वीकार किया जाता है, उन्होंने उक्त तिथि को आरोपित निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त की थी, लेकिन तब भी उन्होंने निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के बाद छह महीने से अधिक समय तक अपील दायर करने के लिए कदम नहीं उठाए और इस लंबी देरी के संबंध में, उनके द्वारा कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और यह आधार कि अपीलकर्ता नंबर 1 के पास वृद्ध व्यक्ति होने के कारण प्रासंगिक अवधि के दौरान यह अपील दायर करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था, विश्वसनीय और स्वीकार्य नहीं है। यह भी कहा गया है कि यह एक स्थापित कानून है कि देरी को माफ करने के विवेक का प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए और तथाकथित पर्याप्त कारण की उदारतापूर्वक व्याख्या नहीं की जा सकती है यदि देरी की माफी

मांगने वाले पक्ष को लापरवाही, निष्क्रियता या सद्भाव की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और ऐसे पक्ष का आचरण, व्यवहार और रवैया उसकी निष्क्रियता या लापरवाही से संबंधित है जो देरी की माफी के लिए उसकी प्रार्थना पर निर्णय लेते समय विचार किए जाने वाले प्रासंगिक कारक हैं और वर्तमान मामले में इस अपील को दायर करने में अपीलकर्ताओं का आचरण उचित नहीं रहा बल्कि वे अपनी अपील दायर करने में पूरी तरह से लापरवाह रहे। इन दलीलों के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मामलों में पारित निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है: -

(I) (2012) 5 एससीसी 157 (मणिबेन देवराज साह बनाम बृहन् मुंबई नगर निगम;

(II) (2013) 12 एससीसी 649 (ईशा भट्टाचार्जी बनाम रघुनाथपुर नफ़र अकादमी की प्रबंध समिति और अन्य;

(III) (2013) 14 एससीसी 81 (बसवराज और अन्य बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी

इन निर्णयों के प्रासंगिक पैराग्राफ, जिन पर भरोसा किया गया है, निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किए जा रहे हैं:-

> <u>मणिबेन देवराज शाह बनाम बृहन् मुंबई नगर निगम, (2012) 5 एससीसी 157</u>
>
> "23. इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि भले ही सीमा अधिनियम की धारा 5 और अन्य समान कानूनों के तहत शक्ति के प्रयोग में उदार और न्यायोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, लेकिन अदालतें इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकती हैं कि सफल वादी ने चुनौती दिए गए फैसले के आधार पर कुछ अधिकार हासिल किए हैं और मुकदमेबाजी के विभिन्न चरणों में लागत के अलावा बहुत समय खर्च होता है।

24. किसी मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स में "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति को क्या रंग मिलेगा, यह काफी हद तक स्पष्टीकरण की सद्भावना पर निर्भर करेगा। यदि न्यायालय पाता है कि आवेदक की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई है और देरी के लिए दिखाए गए कारण में सद्भावना की कमी नहीं है, तो वह देरी को माफ कर सकता है। दूसरी ओर, यदि आवेदक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण मनगढ़ंत पाया जाता है या वह अपने मामले को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से लापरवाह है, तो देरी को माफ न करना विवेक का वैध प्रयोग होगा।

29. दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने कागज़ के गुम हो जाने के बारे में निगम द्वारा गढ़ी गई कहानी में मौजूद खामियों को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया और इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि 7 साल से ज़्यादा समय तक किसी ने फ़ैसले की प्रमाणित प्रतियाँ जारी करने के लिए आवेदन क्यों नहीं किया। हमारे विचार से, अपील दायर करने में देरी के लिए निगम द्वारा दिखाए गए कारण, कम से कम, पूरी तरह से असंतोषजनक थे और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 7 साल से ज़्यादा की देरी को माफ़ करने के लिए बताए गए कारणों को सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत न्यायालय द्वारा विवेक के प्रयोग के लिए खराब माफ़ी के रूप में नहीं माना जा सकता है।

30. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। विवादित आदेश को रद्द किया जाता है और ट्रायल कोर्ट के निर्णयों के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को खारिज किया जाता है। पक्षों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।"

ईशा भट्टाचार्जी बनाम रघुनाथपुर नफ़र अकादमी, (2013) 12 एससीसी 649:

"21. उपर्युक्त प्राधिकारियों से जो सिद्धांत मोटे तौर पर निकाले जा सकते हैं, वे हैं:

21.1. (i) देरी के लिए माफ़ी के आवेदन पर विचार करते समय उदार, व्यावहारिक, न्यायोन्मुख, गैर-पंडितवादी दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि अदालतों से अन्याय को वैध बनाने की अपेक्षा नहीं की जाती है, बल्कि अन्याय को दूर करने का दायित्व है।

21.5. (v) विलम्ब के लिए क्षमा मांगने वाले पक्ष में सद्भावना की कमी एक महत्वपूर्ण और सुसंगत तथ्य है।

21.7.(vii) उदार दृष्टिकोण की अवधारणा में तर्कसंगतता की अवधारणा को समाहित किया जाना चाहिए और इसे पूरी तरह से मुक्त रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

21.9. (ix) किसी पक्षकार की निष्क्रियता या लापरवाही से संबंधित आचरण, व्यवहार और रवैया ऐसे प्रासंगिक कारक हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौलिक सिद्धांत यह है कि न्यायालयों को दोनों पक्षों के संबंध में न्याय के तराजू को तौलना आवश्यक है और उक्त सिद्धांत को उदार दृष्टिकोण के नाम पर पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

21.10. (x) यदि प्रस्तुत स्पष्टीकरण मनगढ़ंत है या आवेदन में दिए गए आधार काल्पनिक हैं, तो न्यायालयों को सतर्क रहना चाहिए कि वे अनावश्यक रूप से दूसरे पक्ष को इस तरह के मुकदमे का सामना करने के लिए उजागर न करें।

21.11. (xi) यह ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति सीमा कानून की तकनीकी बातों का सहारा लेकर धोखाधड़ी, गलत बयानी या हस्तक्षेप से बच नहीं सकता।

22.2. (ख) विलंब की माफी के लिए आवेदन को व्यक्तिगत दर्शन के आधार पर नियमित तरीके से नहीं निपटाया जाना चाहिए जो मूल रूप से व्यक्तिपरक है।

बसवराज बनाम भूमि अधिग्रहण अधिकारी, (2013) 14 एससीसी 81

"7. श्री पाटिल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, ने हमें उच्च न्यायालय के कई निर्णयों से अवगत कराया है, जिनमें सबसे प्रासंगिक कारक अर्थात "पर्याप्त कारण" पर विचार किए बिना देरी को माफ कर दिया गया था, केवल इस शर्त पर कि आवेदकों को देरी की अवधि के लिए ब्याज से वंचित किया जाएगा। इस तरह के निर्णयों को मंजूरी नहीं दी जा सकती। उच्च न्यायालय ऐसे अनुचित और अनावश्यक आदेश पारित करते समय यह समझने में विफल रहा कि वह अधिनियम के तहत अपील पर निर्णय ले रहा था, न कि रिट याचिका पर, जहां असाधारण परिस्थितियों में इस तरह के आदेश को शायद उचित ठहराया जा सकता है।

15. इस मुद्दे पर कानून को इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है कि जहां कोई मामला सीमा से परे अदालत में पेश किया गया है, आवेदक को अदालत को यह बताना होगा कि "पर्याप्त कारण" क्या था, जिसका अर्थ है कि एक पर्याप्त और पर्याप्त कारण जिसने उसे सीमा के भीतर अदालत में जाने से रोका। यदि कोई पक्षकार मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लापरवाह या सद्भावना की कमी का शिकार पाया जाता है, या पाया जाता है कि उसने तत्परता से काम नहीं किया या निष्क्रिय रहा, तो देरी को माफ करने का कोई उचित आधार नहीं हो सकता। कोई भी अदालत किसी भी शर्त को लागू करके इस तरह की

अत्यधिक देरी को माफ करने में उचित नहीं हो सकती। आवेदन पर केवल इस न्यायालय द्वारा देरी की माफी के संबंध में निर्धारित मापदंडों के भीतर ही निर्णय लिया जाना है। यदि किसी वादी को समय पर अदालत में आने से रोकने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो बिना किसी औचित्य के देरी को माफ करना, कोई भी शर्त रखना, वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आदेश पारित करना है और यह विधायिका के प्रति पूर्ण उपेक्षा दिखाने के समान है।

4. दोनों पक्षों को सुना गया।

5. इस न्यायालय का विचार है कि वर्तमान आवेदन में अपीलकर्ताओं द्वारा वर्तमान अपील दायर करने में हुई 187 दिनों की देरी के बारे में बताई गई परिस्थितियाँ उक्त देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त हैं। 17.10.2022 से पहले की अवधि से संबंधित देरी को अपीलकर्ताओं द्वारा वर्तमान याचिका में उचित रूप से समझाया गया है। जहाँ तक 17.10.2022 के बाद की देरी की अवधि का संबंध है, हालाँकि प्रत्येक दिन की देरी के लिए स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन पूरक हलफनामे से दो महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ सामने आती हैं जो दर्शाती हैं कि अपीलकर्ता नंबर 1 जो कि दुख की बात है कि *पैरवीकर* एक वृद्ध व्यक्ति है, देरी की प्रासंगिक अवधि के दौरान बुढापे की बीमारियों से पीड़ित था, दूसरा, वह ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है और तीसरा, उसने यह दलील दी है कि प्रासंगिक अवधि के दौरान अपीलकर्ताओं के पास अपील दायर करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था और धन की व्यवस्था करने में कुछ देरी हुई। हालांकि, ये परिस्थितियां प्रकृति में सामान्य हैं, लेकिन, फिर भी, इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा स्थिति पर विचार करते हुए, यह इस न्यायालय के लिए विश्वास को प्रेरित करती है और यह स्थापित कानून है कि सीमा अधिनियम की धारा 5 विधानमंडल द्वारा अधिनियमित की गई है ताकि

अदालतों को योग्यता के आधार पर मामलों का निपटारा करके पक्षों को पर्याप्त न्याय करने में सक्षम बनाया जा सके और देरी को माफ करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप योग्यता वाले मामलों को बहुत पहले ही खारिज कर दिया जा सकता है और न्याय का कारण विफल हो सकता है और प्रत्येक दिन देरी के स्पष्टीकरण की आवश्यकता का मतलब यह नहीं है कि एक पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इस संबंध में, **कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, अनंतनाग बनाम एमएसटी काटिजी, (1987) 2 एससीसी 107** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत प्रासंगिक है और इसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है: -

> *"विधानसभा ने भारतीय सीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 को अधिनियमित करके विलम्ब को माफ करने की शक्ति प्रदान की है, ताकि न्यायालयों को 'गुण-दोष' के आधार पर मामलों का निपटारा करके पक्षों को पर्याप्त न्याय करने में सक्षम बनाया जा सके। विधानमंडल द्वारा प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'पर्याप्त कारण' न्यायालयों को कानून को सार्थक तरीके से लागू करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त रूप से लचीला है, जो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करता है-जो न्यायालयों की संस्था के अस्तित्व का जीवन-उद्देश्य है। यह सर्वविदित है कि यह न्यायालय इस न्यायालय में स्थापित मामलों में उचित रूप से उदार दृष्टिकोण अपनाता रहा है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह संदेश पदानुक्रम में अन्य सभी न्यायालयों तक नहीं पहुँचा है। और इस तरह का उदार दृष्टिकोण सिद्धांत रूप से अपनाया जाता है क्योंकि यह महसूस किया जाता है कि:*
>
> 1. *आम तौर पर एक वादी को देर से अपील दायर करने से कोई लाभ नहीं होता है।*
> 2. *विलम्ब को माफ करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप एक योग्य मामले को शुरुआत में ही खारिज कर दिया जा सकता है और न्याय का कारण विफल हो सकता है। इसके विपरीत जब विलम्ब को माफ किया जाता है तो सबसे बड़ी बात यह हो सकती है कि किसी मामले का निर्णय पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा।*
> 3. *"हर दिन की देरी का स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए" का अर्थ यह नहीं है कि पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। हर घंटे की देरी, हर सेकंड की देरी क्यों नहीं? इस सिद्धांत को तर्कसंगत सामान्य ज्ञान व्यावहारिक तरीके से लागू किया जाना चाहिए।*
> 4. *जब पर्याप्त न्याय और तकनीकी विचारों को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया जाता है, तो पर्याप्त न्याय के कारण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि दूसरा पक्ष यह*

दावा नहीं कर सकता कि गैर-जानबूझकर की गई देरी के कारण अन्याय होने का उसे अधिकार है।

5.ऐसी कोई धारणा नहीं है कि देरी जानबूझकर, या दोषपूर्ण लापरवाही के कारण, या दुर्भावना के कारण हुई है। देरी का सहारा लेने से वादी को कोई लाभ नहीं होता। वास्तव में वह गंभीर जोखिम उठाता है।

6. यह समझना चाहिए कि न्यायपालिका का सम्मान तकनीकी आधार पर अन्याय को वैध बनाने की उसकी शक्ति के कारण नहीं बल्कि इसलिए किया जाता है क्योंकि वह अन्याय को दूर करने में सक्षम है और उससे ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है।"

6. तदनुसार, यह न्यायालय वर्तमान आई.ए. में अपीलकर्ताओं द्वारा तत्काल अपील दायर करने में देरी के संबंध में दर्शाई गई परिस्थितियों और कारणों से संतुष्ट है और अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए आधार मनगढ़ंत और काल्पनिक नहीं लगते हैं और अपीलकर्ताओं ने निर्धारित सीमा अवधि के भीतर अपनी अपील दायर न करने में पूरी तरह से लापरवाही नहीं की थी, इसलिए, इस अपील को दायर करने में अपीलकर्ताओं की ओर से हुई 187 दिनों की देरी को माफ किया जाता है और तत्काल अंतरिम आवेदन को अनुमति दी जाती है।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

बीकेएस/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।